

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEASI TIMES

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स
इन इंडिया



www.ceasi.in

@ceasi_india



हमारे बारे में

हम कौन हैं:

“सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)” एक स्वायत्त संस्था है, जो “एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)” के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoECRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्कफोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशल युक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- 15+ राज्य
- 15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया
- 20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
- 5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया
- 3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया
- 30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया



CEASI TIMES

फार्म मेकनजेशन इनसाइट्स



ट्रिची के किसानों को श्रम संकट का सामना करने के लिए कृषि यंत्रों का प्रशिक्षण

कृषि अभियंत्रण विभाग ने शुक्रवार को ट्रिची में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसमें किसानों को कृषि यंत्रों के संचालन और रखरखाव के बारे में बताया गया। इसका उद्देश्य मैनुअल श्रम पर निर्भरता कम करना और खेती की लागत को बेहतर बनाना था। जिला कलेक्टर एम. प्रदीप कुमार ने शिविर का उद्घाटन किया और 300 किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों के संचालन व रखरखाव का प्रशिक्षण दिया।

"किसान श्रम की कमी का सामना कर रहे हैं।" मशीनों के उपयोग से लागत में लगभग 30% से 40% तक की कमी आ सकती है," कार्यकारी अभियंता ए. कंथसामी ने कहा।

प्रदर्शन में ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटोवेटर, सीडर, ट्रांसप्लान्टर, वीडर और हार्वेस्टर दिखाए गए। अधिकारियों ने मशीन के विभिन्न हिस्सों को समझने पर जोर दिया, ताकि लंबी अवधि में यंत्र ठीक से काम करें। प्रतिभागियों को ड्रोन और नारियल होइस्टर जैसे उन्नत उपकरणों से भी परिचित कराया गया, जिससे स्मार्ट फार्मिंग तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। यह पहल कृषि को आधुनिक बनाने और दक्षता सुधारने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ग्रामीण श्रम की चुनौतियां हैं।

पराली जलाने की रोकथाम के लिए पंजाब में कस्टम हायरिंग सेंटर होंगे मजबूत

पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs) को मजबूत कर रही है। इसके लिए केंद्र द्वारा मंजूर किए गए ₹500 करोड़ के फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) फंड में से ₹360 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इन सेंटरों पर किसानों को स्ट्रॉ बेलर और रेक जैसी मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी, जो इन-सीटू और एक्स-सीटू तरीके से धान की पराली को संभालने में मदद करती हैं।



60:40 के केंद्र-राज्य फंडिंग मॉडल के तहत 1,000 CHCs इन-सीटू और 500 एक्स-सीटू विधियों के लिए स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र को ₹24 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी।

पंजाब में पराली जलाने के मामलों में गिरावट आई है — 2020 में 76,000 से घटकर 2023 में 36,663 और अब 2024 में केवल 10,909 मामले रह गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले वर्षों में पराली जलाने को पूरी तरह खत्म करने के लिए मशीनों में निवेश और भूसे के व्यापार को बढ़ावा देना जरूरी है।

इसके अलावा, 4,367 मशीनें — जिनमें सुपर सीडर और बेलर शामिल हैं — किसानों को वितरित की जाएंगी। एक्स-सीटू यूनिट्स के लिए अतिरिक्त ₹30 करोड़ आवंटित किए गए हैं ताकि भूसे का उपयोग बायोमास और कम्पोस्ट उद्योगों में बढ़ाया जा सके।

CEASI TIMES

गुजरात में किसानों को सशक्त बनाने के लिए 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' शुरू

गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी कृषि तकनीकों व तरीकों को पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से बढ़ावा देना है। यह विशेष अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा और इसका मुख्य मकसद वैज्ञानिक उपायों के ज़रिए खेती की पैदावार को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।



इस पहल में किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और केंद्र व राज्य सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। अभियान में ड्रोन तकनीक और नैनो यूरिया का उपयोग कर टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना, उत्पादकता में सुधार और नवाचार व ज्ञान साझा करके किसानों की आजीविका को मजबूत करना शामिल है।

इस अभियान के दौरान 55 विशेषज्ञ टीमों द्वारा गांवों का दौरा किया जाएगा, जहां वे 3.5 लाख से अधिक किसानों को उन्नत कृषि तरीकों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इसमें कृषि यंत्रीकरण, प्राकृतिक और जलवायु अनुकूल खेती, उन्नत बीज और सटीक खाद उपयोग (जैसे नैनो उर्वरक) को अपनाने पर जोर दिया गया है।



उत्तरी युगांडा में 1,500 छोटे किसानों को मिलेगा यंत्रीकरण का सहारा

न्यू एनर्जी नेक्सस युगांडा की एक नई पहल उत्तरी युगांडा के 1,500 छोटे और सीमांत किसानों की कृषि उत्पादकता को बेहतर ढंग से बढ़ाने के लिए यंत्रीकरण उपकरणों की सुविधा प्रदान कर रही है। "कृषि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादक उपयोग" नामक यह विशेष कार्यक्रम किसानों को सिंचाई, अनाज पिसाई, फसल सुखाने और अन्य कृषि कार्यों के लिए जरूरी उपकरणों की सहायता उपलब्ध करता है।

इस योजना के अंतर्गत अचोली उपक्षेत्र के किसान केवल 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करके उपकरण प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बाकी राशि सालाना 14 प्रतिशत ब्याज दर पर तिमाही किस्तों में चुकानी होगी। यह लचीला भुगतान मॉडल खेती के चक्र से जुड़ा हुआ है, जिससे किसान फसल की कटाई और बिक्री के बाद भुगतान कर सकते हैं।

यह कार्यक्रम तुलीमा सोलर, मर्सी कॉर्प्स और नुटोफा के सहयोग से चलाया जा रहा है और संगठित किसान समूहों को उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। किसान क्रिस्टीन अमोनी जैसी महिलाएं बताती हैं कि बेहतर उपकरणों से कामकाज में तेजी आती है और खेती को ज्यादा टिकाऊ और लाभदायक बनाया जा सकता है।

CEASI TIMES

हॉर्टिकल्चर इनसाइट्स



मालदा में आम और लीची के बागानों में अंतरवर्तीय खेती (Intercropping) को बढ़ावा

टिकाऊ कृषि और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में मालदा के बागवानी विभाग ने आम और लीची के बागानों में सह फसली खेती, जिसे अंतरवर्तीय खेती भी कहा जाता है, को बढ़ावा देना शुरू किया है। हाल ही में स्थानीय किसानों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जैविक खेती और भूमि के सही उपयोग पर ज़ोर दिया गया।

किसानों को रासायनिक खादों का उपयोग कम करने और उनके जैविक विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि फलों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस पहल का उद्देश्य बागवानी को एक टिकाऊ और आर्थिक रूप से फायदेमंद मॉडल में बदलना है। क्षेत्र में 200 से अधिक नए आम बागान और लगभग 100 लीची के बाग लगाए गए हैं। किसानों को पेड़ों के बीच की खाली जमीन में कम समय में तैयार होने वाली सब्जियां और मसालों की खेती के तरीके सिखाए गए।

फसलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया — अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक। हल्दी, अदरक और जिमीकंद जैसे फसलें पुराने बागानों में उपयुक्त हैं; नींबू, पपीता और केला जैसे फलों की खेती नए बागानों में की जा सकती है; जबकि कटहल, चीकू और नींबू जैसी दीर्घकालिक फसलें लंबे समय में लाभ देती हैं। प्रमुख ब्लॉकों से आए किसानों ने इस तकनीक को अपनाने में गहरी रुचि दिखाई और सक्रिय भागीदारी की।

किसानों को सशक्त बनाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय कार्यक्रम शुरू

“विकसित कृषि संकल्प अभियान” के तहत 15 दिवसीय जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत पश्चिम गोदावरी जिले के पट्टिमपलेम गांव में हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसमें रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और जैविक नियंत्रण आधारित प्रबंधन को अपनाने पर ज़ोर दिया गया, ताकि पर्यावरण और फसल स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके।



कार्यक्रम में बागवानी क्षेत्र की भूमिका को पोषण सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण बताया गया। अधिकारियों ने संतुलित उर्वरक उपयोग और मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार फसल चयन पर बल दिया ताकि दीर्घकालिक उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके।

कृषि संस्थानों के विशेषज्ञों ने खरीफ सीजन के लिए समन्वित रणनीतियों पर चर्चा की, जिसमें हल्दी, अरंडी और अश्वगंधा में मूल्य संवर्धन, प्राकृतिक खेती और ऑयल पाम की खेती शामिल रही। कार्यक्रम में स्मार्ट खेती पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें आईसीटी उपकरणों और ड्रोन तकनीक के उपयोग को समझाया गया। 400 से अधिक किसान, गांव प्रमुख और अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हुई।

CEASI TIMES

स्वास्थ्य, टिकाऊ जीवन और शहरी भलाई के लिए एफटीसीसीआई ने किया किचन गार्डनिंग को बढ़ावा

तेलंगाना चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FTCCI) की एग्री और फूड प्रोसेसिंग कमेटी ने हाल ही में "ग्रो योर ओन फूड" नामक एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। इस सत्र का उद्देश्य किचन गार्डनिंग को बढ़ावा देना था, जिससे लोगों का आहार सुधरे और शहरी तनाव कम हो सके। इसमें शहरी निवासियों को बालकनी और खिड़कियों जैसे छोटे स्थानों में रासायन मुक्त बागवानी के लिए प्रेरित किया गया।



विशेषज्ञों ने बताया कि घर पर उगाए गए फल-सब्जियां न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करती हैं और व्यक्ति को प्रकृति तथा आत्म-देखभाल से जोड़ती हैं।

सत्र में किचन गार्डनिंग, जैविक कीट नियंत्रण और कंपोस्टिंग के व्यावहारिक सुझाव साझा किए गए। इसमें ताज़ी उपज से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों पर ज़ोर दिया गया और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रसायनों के कम उपयोग को बढ़ावा दिया गया। किचन गार्डनिंग को समग्र स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया।



पोल्लाची नारियल क्लस्टर के विकास के लिए ₹250 करोड़ का परियोजना शुरू

इस योजना के लिए पात्र क्रियान्वयन एजेंसियों में किसान उत्पादक संगठन (FPOs), सहकारी समितियां, निजी कंपनियां, सरकारी विभाग और केंद्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान शामिल हैं। तमिलनाडु बागवानी विकास एजेंसी (TANHODA) 25 जून, 2025 तक ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित कर रही है।

नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) के तहत पोल्लाची नारियल क्लस्टर के समग्र विकास के लिए ₹250 करोड़ की केंद्रीय सरकार की परियोजना हाल ही में शुरू की गई है। इस परियोजना में कुल ₹100 करोड़ की महत्वपूर्ण सब्सिडी शामिल है और इसका ध्यान तीन मुख्य क्षेत्रों पर विशेष रूप से होगा: उत्पादन पूर्व और उत्पादन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन, तथा लॉजिस्टिक्स, विपणन और ब्रांडिंग।

पोल्लाची क्लस्टर, जो 15,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला एक 'मेगा' पायलट प्रोजेक्ट है, देश के 12 क्लस्टरों में से एक है। ₹75 लाख की मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है, जो हर महीने 12 गांवों में कैंप आयोजित करेगी, किसानों को मिट्टी के आधार पर उर्वरक उपयोग की सलाह देगी और नाम मात्र शुल्क पर मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी करेगी।

CEASI TIMES

डेयरी इनसाइट्स



नागालैंड में दुग्ध क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन योजनाओं की समीक्षा

भारत सरकार के पशुपालन और दुग्ध विभाग (DAHD) के अनुभवी और राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षकों (NLMs) ने नागालैंड में 28 से 31 मई तक विभिन्न केंद्रीय पशुपालन योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। इस मूल्यांकन में विशेष रूप से राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम (NPDD), राष्ट्रीय गो-कुल मिशन (RGM), और राष्ट्रीय पशुपालन मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान और गहराई से जांच की गई।

यह समीक्षा पेरेन और डिमापुर जिलों में की गई। कोहिमा में राज्य स्तरीय ब्रीफिंग भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा के आयुक्त और सचिव ने की। इस ब्रीफिंग में DAHD के अधिकारी, राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और राज्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए।

समीक्षा का मुख्य फोकस दूध उत्पादन, देशी नस्लों के संवर्धन और पशु स्वास्थ्य पर था। पर्यवेक्षकों ने क्षेत्रीय दौरे किए, दुग्ध उद्यमियों से बातचीत की और कार्यप्रणालियों का मूल्यांकन किया ताकि बेहतर नीति और संचालन सुधारों के लिए सुझाव दिए जा सकें और इस क्षेत्र के विकास में मदद मिल सके।

गोवा में पहला पशु चिकित्सा कॉलेज खुलेगा, पशुपालन मजबूत होगा

गोवा अपने पहले पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना करने जा रहा है, ताकि दुग्ध और पशुपालन क्षेत्रों को बेहतर समर्थन मिल सके। गोवा कॉलेज ऑफ़ वेटेरनरी एंड एनिमल साइंसेज कुरटी, पोंडा में 66,595 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगा, जो वर्तमान में पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय के अधीन है। यह भूमि और सुविधाएं नए संस्थान को 10 साल के लिए पट्टे पर दी गई हैं।



यह पहल पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन को बेहतर बनाने और राज्य में टिकाऊ पशुपालन प्रथाओं को बढ़ावा देने की उम्मीद रखती है। मुख्य तैयारियों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन, प्रयोगशालाओं और पशु फार्मों का विकास, और योग्य कर्मचारियों की भर्ती शामिल है।

एक प्रमुख पशु चिकित्सा संस्थान से सेवानिवृत्त प्रोफेसर को पहले डीन के रूप में नियुक्त किया गया है।

इस विकास से गोवा की पशु चिकित्सा शिक्षा क्षमता मजबूत होगी और पशुपालन तथा दुग्ध उद्योगों के विकास में मदद मिलेगी। यह कॉलेज स्थानीय स्तर पर पशु चिकित्सा शिक्षा की मांग को पूरा करेगा, क्योंकि पहले गोवा के छात्र अन्य राज्यों में पढ़ाई करते थे। आगामी शैक्षणिक वर्ष से यह कॉलेज बैचलर ऑफ़ वेटेरनरी साइंस एंड एनिमल हल्थ (BVSc & AH) कार्यक्रम शुरू करेगा।

CEASI TIMES

हरियाणा ने दुग्ध और पशुपालन विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया

हरियाणा ने कुरुक्षेत्र से 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य कृषि को टिकाऊ बनाना और दुग्ध एवं पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करना है। यह अभियान वैज्ञानिक तरीकों, उन्नत तकनीकों और पशुपालन सेवाओं की बेहतर पहुंच को बढ़ावा देता है। प्रमुख कृषि विभागों के संयुक्त नेतृत्व में यह पहल समेकित खेती को प्रोत्साहित करती है।



यह अभियान 109 ब्लॉकों के 1,380 गांवों तक पहुंचेगा, जहां पशुपालन देखभाल, चारा विकास, पशु चिकित्सा सेवाएं और टिकाऊ दुग्ध प्रथाओं पर स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन दिया जाएगा।

यह अभियान 12 जून तक जारी रहेगा और इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को जमीन पर लागू करना है। किसानों को प्रमुख केंद्रीय और राज्य योजनाओं, जैसे फसल बीमा और देशी पशुओं के लिए प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभियान में प्राकृतिक दुग्ध उत्पादन और डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि पशुपालन प्रबंधन में सुधार हो सके।



ओडिशा ने दुग्ध किसानों के लिए समर्थन बढ़ाया, दूध खरीद मूल्य में वृद्धि की

विश्व दूध दिवस पर, ओडिशा सरकार ने ओएमएफेड से जुड़े दूध उत्पादकों के लिए ₹1 लाख की आकस्मिक मृत्यु सहायता की घोषणा की और दूध की खरीद मूल्य में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। खुदरा दूध की कीमतों में ₹4 प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी, जिसमें से ₹2 का सब्सिडी सरकार देगी और ₹2 उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाएगा। ओडिशा ने 2023-24 में 26.4 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन किया, लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता केवल 156 ग्राम है, जो राष्ट्रीय औसत 471 ग्राम से काफी कम है।

राज्य का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में उत्पादन दोगुना करना है। इसके लिए मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के तहत दुग्ध किसानों को 70% तक वित्तीय सहायता दी जाती है, और मुख्यमंत्री प्राणी कल्याण योजना के तहत गोशालाओं को पशु देखभाल के लिए अनुदान मिलता है।

इस अवसर पर तीन नए ओएमएफेड दुग्ध उत्पाद भी लॉन्च किए गए। ये कदम दुग्ध अवसंरचना को मजबूत करने, पशु कल्याण का समर्थन करने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं, जिससे पोषण स्तर सुधरेगा और ग्रामीण आजीविका बेहतर होगी।

CEASI TIMES

जनरल एग्रीकल्चर इनसाइट्स

Boost to kharif crops
MSP (₹/quintal)

	2024-25	2025-26	% change
Paddy gr A	2,320	2,389	3.0
Jowar	3,371	3,699	9.7
Bajra	2,625	2,775	5.7
Maize	2,225	2,400	7.9
Ragi	4,290	4,886	13.9
Urad	7,400	7,800	5.4
Tur	7,550	8,000	6.0
Moong	8,682	8,768	1.0
Soyabean	4,892	5,328	8.9
Groundnut	6,783	7,263	7.1
Sunflower	7,280	7,721	6.1
Cotton (long)	7,521	8,110	7.8
Cotton (medium)	7,121	7,710	8.3
Sesame	9,267	9,846	6.2
Niger	8,717	9,537	9.4
Paddy	2,300	2,369	3.0

Source: CACP



सोयाबीन एमएसपी बढ़ोतरी से खरीफ 2025 में क्षेत्र स्थिर

सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का समय पर महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिससे खरीफ 2025 के सीजन में किसानों का मनोबल काफी मजबूत हुआ है और मक्का की तरफ बड़े पैमाने पर बदलाव की चिंता काफी कम हुई है। MSP में ₹436 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, जो ₹4,892 से बढ़कर ₹5,328 हो गई है। यह खरीफ की मुख्य तिलहन फसलों में सबसे ज्यादा 8.9% की वृद्धि है।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के किसान पहले मक्का की ओर झुकाव दिखा रहे थे, क्योंकि मक्का की लागत कम है और यह अनियमित बारिश में भी अच्छी फसल देता है। लेकिन सोयाबीन के MSP बढ़ने से तेल बीज की खेती में रुचि बढ़ी है, जिससे आयात कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मक्का को भी MSP में 7.9% की बढ़ोतरी मिली है। फिर भी शुरुआती बुवाई के रुझान बताते हैं कि सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल ज्यादातर बना रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को आगे भी खरीदारी के प्रयास करने चाहिए ताकि किसानों को नए MSP का पूरा लाभ मिल सके और फसलों के स्थायी विविधीकरण को बढ़ावा मिले।

राष्ट्रीय वीड मैनेजमेंट नीति से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की मांग

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें नीति निर्माता, शोधकर्ता और कृषि उद्योग के प्रमुख शामिल हुए। इस आयोजन का विषय था “नेशनल वीड मैनेजमेंट नीति: किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक।” इस कार्यक्रम में भारत में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली जंगली घास की समस्या को जल्द से जल्द हल करने की जरूरी आवश्यकता पर जोर दिया गया।

कृषि अनुसंधान परिषद के जंगली घास अनुसंधान निदेशालय और किसान विज्ञान फाउंडेशन के विशेषज्ञों ने टिकाऊ जंगली घास प्रबंधन, जंगली घास में दवा प्रतिरोध रोकने और तकनीकी नवाचार पर अपने शोध प्रस्तुत किए।

गोलमेज सम्मेलन में विज्ञान आधारित और किसान केंद्रित वीड मैनेजमेंट नीति बनाने का सुझाव दिया गया, जिसमें दवा प्रतिरोध नियंत्रण के लिए समिति, दवाओं के पंजीकरण में सुधार, समेकित प्रबंधन और सटीक खेती के उपकरण शामिल हों।

वक्ताओं ने कहा कि प्रभावी वीड नियंत्रण से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और भारत की बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।



CEASI TIMES

उत्तराखंड में 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' की शुरुआत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गंजयाल गांव में 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' का भव्य शुभारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि को आधुनिक बनाना और उत्तराखंड के सभी किसानों को समुचित समर्थन देना है। इस व्यापक अभियान में कृषि वैज्ञानिक और संबंधित अधिकारी 95 विकास खंडों, 670 न्याय पंचायतों और 11,000 से अधिक गांवों के किसानों तक पहुंचकर उनकी मदद करेंगे।



किसानों को कृषि, पशुपालन और बागवानी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिसमें उनकी प्रतिक्रिया, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय नवाचारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समर्थन में ब्याज मुक्त ऋण, उपकरणों पर सब्सिडी, सिंचाई सहायता और फसल बोनस शामिल हैं। खास निवेश जैविक खेती, सुगंध घाटी और पॉलीहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित होगा।

29 मई से 12 जून तक, 2,000 से अधिक टीमों देशभर में 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेंगी। उत्तराखंड में प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित कर 600 किसानों को जलवायु-स्मार्ट खेती, मिट्टी परीक्षण और फसल चयन के बारे में जानकारी दी जाएगी।



उत्तर प्रदेश में 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के तहत 50 लाख किसानों तक पहुंच का लक्ष्य

केंद्र सरकार द्वारा संचालित 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के तहत उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है कि वह कम से कम 50 लाख किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करे। यह संख्या पूरे देश के 1.5 करोड़ किसानों के लक्ष्य का लगभग एक-तिहाई है। उत्तर प्रदेश, जो देश की कुल खाद्यान्न उत्पादन का 22% हिस्सा देता है जबकि इसके पास केवल 11% कृषि भूमि है, अब वैज्ञानिक जागरूकता, टिकाऊ खेती और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रहा है।

यह अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा और राज्य के 723 जिलों के 65,000 गांवों को कवर करेगा। इसमें खरीफ फसलों की तकनीक, प्राकृतिक खेती और पर्यावरणीय लाभों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रयास को उत्तर प्रदेश 'किसान कल्याण केंद्रों', 'किसान पाठशालाओं', 'मिलियन फार्मर्स स्कूल्स' और 89 'कृषि विज्ञान केंद्रों' (केवीके) के माध्यम से समर्थन देगा, जिनमें से 18 को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।

ये कृषि विज्ञान केंद्र जिलेवार दिशा-निर्देश देंगे, जैसे कि उन्नत बीज, मिट्टी की सेहत, सिंचाई तकनीक, ड्रोन का उपयोग और फसल सुरक्षा। अभियान के तहत पीएम-किसान, किसान रजिस्ट्रेशन और फसल बीमा योजना जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की भलाई और कृषि उत्पादकता दोनों में सुधार हो सके।

CEASI एक्टिविटीज

क्लस्टर फार्मिंग और बागवानी प्रबंधन प्रशिक्षण के माध्यम से करनाल में महिला किसानों को सशक्त बनाना

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI) ने एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषित HP-SHIVA परियोजना के अंतर्गत 30 महिला किसानों को लक्षित करते हुए 26 से 28 मई तक करनाल में एक 3-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण-सह-अभ्यास कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह प्रशिक्षण क्लस्टर फार्मिंग, एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) विकास और बागवानी प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास और सतत कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करके सशक्त बनाना है।

इस पहल के तहत प्रतिभागियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें सैद्धांतिक सत्र, व्यावहारिक प्रशिक्षण, रोलप्ले और उन्नत तकनीकों से परिचय शामिल था। इसके साथ ही, कुरुक्षेत्र स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र और लाडवा स्थित उप-उष्णकटिबंधीय फल केंद्र का दौरा भी करवाया गया, जिससे प्रतिभागियों को परागण प्रबंधन, सतत बागवानी प्रथाओं और सामूहिक खेती के तरीकों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला किसानों को आवश्यक ज्ञान, तकनीकी कौशल और आत्मविश्वास से लैस करना है ताकि वे अपने समुदायों में नवाचारी और व्यावहारिक कृषि तकनीकों को अपनाकर दीर्घकालिक कृषि स्थिरता और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा दे सकें।

